आम लोग एक साथ पाएंगे अपने लाभ वाली सभी योजनाओं की जानकारी

ईज ऑफ लिविंग के अंतर्गत नया सिस्टम विकसित करने का फरमान

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश सरकार आम लोगों को उनकी पात्रता वाली सरकारी लाभ की समस्त योजनाओं की जानकारी एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए नया सिस्टम विकसित करने की तैयारी कर रही है। पहले चरण में आम जनमानस से जुड़ी आठ से दस विभागों की योजनाओं को शामिल करने का प्रस्ताव है। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग को इस संबंध में कार्यवाही का निर्देश दिया गया है।

जनधन, अटल पेंशन व दुर्घटना बीमा जैसी आठ से दस योजनाएं जुड़ेंगी

प्रदेश सरकार आम लोगों के दैनिक कामकाज व लाभ प्राप्त करने में आने वाली मुश्किलों को आसान बनाने के लिए 'ईज ऑफ लिविंग' योजना पर काम कर रही है। कारोबारी सुधार एक्शन प्लान-2022 में ऐसा तंत्र विकसित करने को कहा गया है जिस पर लोग अपनी आयु, शिक्षा व आय आदि का विवरण अपलोड कर यह जान लें कि सरकार की किन-किन योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सकता है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने जनधन योजना, अटल पेंशन योजना व दुर्घटना बीमा सहित विभिन्न विभागों की 8-10 योजनाओं को चिह्नित कर सिस्टम विकसित करने को कहा है।

आवेदन के साथ डिजीलॉकर से डॉक्यूमेंट कर सकेंगे लिंक

आवेदन पत्रों के साथ आवश्यक अभिलेख ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए संबंधित पोर्टल से डिजीलॉकर को लिंक किया जाएगा। कई विभाग विभिन्न योजनाओं से संबंधित आवेदन पत्रों के साथ सर्टिफिकेट अपलोड करने को कहते हैं। स्कैन कर अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट का सत्यापन करना पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए आवेदन से संबंधित पोर्टल पर आवेदन पत्र में डिजी लॉकर से सर्टिफिकेट लिंक/फेच करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इससे सत्यापित डॉक्यूमेंट का लिंक आवेदन के साथ ही उपलब्ध हो सकेगा।

औद्योगिक विकास विभाग को मिली जिम्मेदारी

प्रदेश में बिजनेस रिफार्म एक्शन प्लान (बीआरएपी) व ईज ऑफ लिविंग से संबंधित विभिन्न विभागों से समन्वय की कार्यवाही वर्तमान में अलग-अलग विभाग कर रहे हैं। बीआरएपी के अंतर्गत समस्त कार्यवाही अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, जबकि ईज ऑफ लिविंग रिफार्म से संबंधित सभी कार्यवाही नियोजन विभाग कर रहा है। मुख्य सचिव ने ईज ऑफ लिविंग रिफार्म से संबंधित सभी तरह की कार्यवाही तथा विभागों से समन्वय व समीक्षा की जिम्मेदारी भी अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग को दे दी है।

श्रमिकों की योजनाओं पर फोकस करेगी सरकार

लखनऊ। श्रमिकों की कल्याणकारी योजनाओं पर सरकार और गंभीरता से फोकस करने जा रही है। इस बाबत उन श्रमिकों का डाटा एकत्र किया जा रहा है जो सरकार की योजनाओं से महरूम रह गए।

दरअसल प्रदेश सरकार अपने संकल्प पत्र के 100 दिन की कार्ययोजना तैयार कर रही है। इसमें श्रम विभाग के श्रमिकों को भी लाभ देने का रोडमैप तैयार करने को कहा गया है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड श्रमिकों के हित में चलाई जा रही योजनाओं को और प्रभावी बनाएगा। इस बाबत मंत्री अनिल राजभर ने भी बैठक लेकर निर्देश दिए थे कि बोर्ड की सभी योजनाओं को प्रत्येक श्रमिक तक पहुंचाया जाए। इनमें पुनर्वास, बाल श्रम एवं बंधुवा श्रम का उन्मूलन जैसे कार्यक्रमों को सबसे ज्यादा प्रभावी ढंग से लागू करने की योजना है। इस बाबत 100 दिन का प्रजेंटेशन भी तैयार किया गया है। ब्यूरो